3 खाद्य विभाग की कार्रवाई, 338 किलो घी जब्त

5 दीपके बने युवा-केंद्रित आंदोलन के संस्थापक

6 कश्मीर में हिंदुओं पर लक्षित हमला

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 12 प्रति सोमवार, 10 अगस्त 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

भिलाई स्टील प्लांट में सेंधमारी

40 वर्षों से करोड़ों का लोहा चोरी कर रहे इंद्रजीत और उनका परिवार! आखिर 1500 ट्रकों का मालिक कैसे बना इंद्रजीत?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में पिछले 40 वर्षों से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लोहे की चोरी होने का दावा किया गया है। इस मामले ने तब बड़ा रूप ले लिया जब दुर्ग पुलिस ने भिलाई में बड़े पैमाने पर हो रहे एक संगठित लोहा चोरी रैकेट का पर्दाफाश किया। लोहा चोरी का काम पहले इंद्रजीत उर्फ छोटू के पिता दलवीर सिंह उर्फ़ वीरा सिंह करते थे। पिता के मरने के बाद बेटा इन्द्रजीत सिंह इस काम को अंजाम दे रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरा सिंह पहले सुअरों को भी काट-काट कर बेचते थे। इंद्रजीत सिंह के दादा स्वर्ण सिंह भिलाई स्टील प्लांट में कर्मचारी थे। दलवीर सिंह भिलाई सेक्टर 6 के मार्केट में 1985-86 में गन्ना का रस बेचते थे फिर उन्होंने एक

ट्रक ख़रीदा। उसे भिलाई स्टील प्लांट में चलाने लगे। फिर कबाड़ के धंधे में उतर गये। भिलाई स्टील प्लांट में सीआईएसएफ और पुलिस की मदद से लोहा चोरी का साम्राज्य खड़ा कर लिया। देखते-देखते बहुत बड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट कम्पनी HTC बना ली और हेवी ट्रांसपोर्टर बन गये। जितने भी दो नम्बर के काम करते हैं उसके लिए ड्राइवरों के नाम पर ही ट्रक खरीद लेते थे या ड्राईवर और सुपरवाईजरों को ट्रक भाड़े के एग्रीमेंट करके दे देते थे, जिससे जब चोरी का लोहा पकड़ा जाय तो ड्राईवर और सुपरवाईजर पकड़ा जाय। प्लांट से जितना भी लोहा चोरी करके लाया जाता है उसके बाद लोहा छोटू के यार्ड में उतारा जाता है। उसका 15% मार्केट मूल्य के हिसाब से लोहा चोर ड्राइवर या सुपरवाईजर को छोटू का आदमी भुगतान कर देता है। बाकी माल छोटू मार्केट में फर्जी बिलों के जरिये बेच देते हैं। लोहा चोरी करने के लिए सीआईएसएफ के अधिकारियों और सिपाहियों और मार्केटिंग टीम से मिलीभगत कर ली जाती है। (शेष पेज 6 पर)

साय सरकार के प्रयासों से धमतरी बना आत्मनिर्भर गांवों का मॉडल

औषधीय खेती से बदली तस्वीर, महिलाओं के हाथों में आई समृद्धि की कमान

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। कभी अनुपयोगी पड़ी जमीन, घरों की खाली बाड़ियां और कम उत्पादक क्षेत्र अब औषधीय एवं सुगंधीय पौधों की हरियाली से गुलजार हो रहे हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत गांव की महिलाएं बनी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों, किसानों और ग्रामीण समुदायों को स्थानीय संसाधनों से जोड़कर आय के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। धमतरी जिले में औषधीय एवं सुगंधीय फसलों के कृषिकरण की पहल इसी बदलाव की एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर उभरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान', राज्य औषधीय पादप बोर्ड तथा जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से शुरू हुई इस पहल ने खेती को केवल उत्पादन का माध्यम न मानकर ग्रामीण आजीविका और महिला उद्यमिता से जोड़ने का रास्ता तैयार किया है। (शेष पेज 2 पर)

क्या चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव कांग्रेस की संजीवनी बनकर उभरेंगे?

2028 की तैयारी, कांग्रेस फिर खेल सकती है अनुभव पर दांव

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में 2028 के विधानसभा चुनावों की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। बीजेपी जहां सरकार में रहते हुए अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने में सक्रिय दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर संगठनात्मक पुनर्गठन और नेतृत्व की नई जिम्मेदारियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि कांग्रेस आलाकमान एक बार फिर अनुभवी और संतुलित नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष रह चुके वरिष्ठ नेता डॉ. चरणदास महंत और पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. टी.एस. सिंहदेव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप सकता है। (शेष पेज 3 पर)

कमलनाथ के विजन को ही पूरा कर रही मोदी सरकार

भारत के आधुनिक सड़क विकास के शिल्पकार हैं कमलनाथ

-विजया पाठक

भारत के आर्थिक विकास की सबसे मजबूत आधारशिला यदि किसी क्षेत्र ने तैयार की है तो वह देश का सड़क एवं परिवहन नेटवर्क है। सड़कें केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का साधन नहीं होतीं, बल्कि वे विकास, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार की जीवनरेखा होती हैं। पिछले तीन दशकों में भारत में सड़क अवसंरचना के जिस व्यापक विस्तार की शुरुआत हुई, उसमें अनेक नेताओं और सरकारों का योगदान रहा है। इन्हीं प्रमुख नेताओं में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी उल्लेखनीय है। (शेष पेज 5 पर)

श्रमिकों के कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए: अर्जुन सिंह

-अमित राय

जगत प्रवाह. दार्जिलिंग। सिन्कोना निदेशालय की प्रशासनिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल सरकार में श्रम और परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने की। बैठक में दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट, पर्यटन मंत्री डॉ. शंकर घोष, गृह और पहाड़ी मामलों विभाग के राज्य मंत्री विशाल लामा, क्षेत्र के निर्वाचित विधायक, श्रम विभाग के प्रधान सचिव, जीटीए के प्रधान सचिव, जिलाधिकारी, सिन्कोना निदेशक, सीएमओएच और राज्य व जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में सिन्कोना बागानों के श्रमिकों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, पीने के पानी और आवास की व्यवस्था, 'पर्चा पट्टा' (भूमि अधिकार), वेतन और अन्य भत्तों में समय पर संशोधन, महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान न होना, सिन्कोना बागानों में विविधता और आधुनिकीकरण की कमी, और सभी खाली पदों पर समय पर नियुक्ति जैसे मुद्दे शामिल थे। वहीं मंत्री अर्जुन सिंह ने श्रम विभाग के प्रधान सचिव और जिलाधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के कल्याण से जुड़े मुद्दों- जैसे वेतन संशोधन, डीए और संबंधित मामले को प्राथमिकता दी जाए। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार सिन्कोना बागान को आधुनिक बनाने और उसे फिर से जीवंत करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिसे आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा। जिससे बागानों को फिर से बेहतर बनाया जा सके।

औषधीय खेती से बदली तस्वीर, महिलाओं के हाथों में आई समृद्धि की कमान

(पेज 1 का शेष)

अनुपयोगी जमीन बनी आय का जरिया

धमतरी कृषि प्रधान जिला है और यहां बड़ी आबादी पारंपरिक रूप से धान की खेती पर निर्भर रही है। लेकिन सीमित आय, मौसम की अनिश्चितता और कई क्षेत्रों में अनुपयोगी अथवा कम उत्पादक भूमि किसानों के सामने चुनौती रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैकल्पिक कृषि गतिविधियों की संभावनाएं तलाशीं। रेतीली जमीन, कटाव प्रभावित क्षेत्र और कम उत्पादक भूमि पर खस, ब्राह्मी, बच, लेमनग्रास, पामारोजा और पचौली जैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया गया। इन फसलों का चयन इस दृष्टि से किया गया कि कम उत्पादक भूमि को भी आर्थिक गतिविधि से जोड़ा जा सके और किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ अतिरिक्त आय का विकल्प मिले। इस पहल की खास बात यह रही कि महिलाओं को इसके केंद्र में रखा गया। महिला स्व-सहायता समूहों को पौध सामग्री, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया। इससे खेती के साथ-साथ समूह प्रबंधन, बैंकिंग, विपणन और उद्यमिता के नए अवसर भी महिलाओं के सामने आए।

मुख्यमंत्री साय की प्राथमिकताओं से जुड़ा मॉडल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। 'लखपति दीदी' की अवधारणा इसी व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसमें महिलाओं को केवल सहायता प्राप्त करने वाली लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों की संचालक और उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। धमतरी का औषधीय खेती मॉडल इस सोच को जमीन पर उतारने का उदाहरण बन रहा है। यहां महिला समूहों को खेती से जोड़ने के साथ बाजार की जरूरतों के अनुरूप फसलों का चयन किया गया। पौध सामग्री से लेकर प्रशिक्षण और खरीद की व्यवस्था तक एक समन्वित व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया। सरकार की यह सोच ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जब किसी परिवार में महिला की अपनी नियमित आय होती है तो उसका असर केवल घरेलू अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि निवेश और परिवार के भविष्य से जुड़े निर्णयों में महिलाओं की भूमिका मजबूत होती है।

150 एकड़ से शुरू हुई पहल ने बढ़ाया भरोसा

इस अभियान के शुरुआती चरण में करीब 150 एकड़ क्षेत्र में लगभग 200 महिला स्व-सहायता समूह सदस्यों को जोड़ा गया। करीब 80 एकड़ में खस, 20 एकड़ में ब्राह्मी, 10 एकड़ में बच तथा लगभग 40 एकड़ में लेमनग्रास, पामारोजा और पचौली जैसी फसलों का रोपण किया गया। शुरुआती परिणामों ने किसानों और महिला समूहों का भरोसा बढ़ाया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ क्षेत्रों में औषधीय फसलों से प्रति एकड़ लगभग एक लाख रुपये तक की आय के उदाहरण सामने आए हैं। हालांकि वास्तविक आय फसल, लागत, उपज, बाजार मूल्य और खेती की परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। इस अतिरिक्त आय ने ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में भूमिका निभाई है। कई महिलाओं ने अपनी आमदनी का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों, कृषि उपकरणों और छोटे व्यवसायों में किया। इससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी मिला है।

महिलाओं को किसान से उद्यमी बनाने की दिशा

धमतरी की पहल का महत्व इस बात में भी है कि इसमें महिला समूहों को केवल खेत तक सीमित रखने के बजाय उन्हें पूरी मूल्य श्रृंखला से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। कुरूद विकासखंड के कोटगांव और पचपेड़ी में औषधीय पौधों की नर्सरी विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर पौध सामग्री तैयार होने से किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त पौधे मिल सकेंगे। आगे प्रसंस्करण, आवश्यक तेल निकालने, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन की संभावनाएं भी विकसित की जा रही हैं। यदि इन गतिविधियों का विस्तार होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। यानी सरकार का प्रयास केवल 'उगाने' तक सीमित नहीं रहकर 'उगाने से लेकर बेचने और मूल्य बढ़ाने' तक की व्यवस्था तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है। यही किसी कृषि मॉडल को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी है।

'लखपति दीदी' अभियान को मिल रहा आधार

छत्तीसगढ़ में महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के प्रयासों के बीच धमतरी की औषधीय खेती नई संभावनाएं पैदा कर रही है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को ऐसी गतिविधियों से जोड़ना है, जिनसे उनकी आय में स्थायी वृद्धि हो सके। औषधीय और सुगंधीय फसलों की खेती इस लिहाज से उपयोगी विकल्प बन सकती है, क्योंकि यह पारंपरिक धान आधारित कृषि के साथ अतिरिक्त गतिविधि के रूप में भी अपनाई जा सकती है। इससे किसानों को अपनी भूमि और उपलब्ध संसाधनों का विविध उपयोग करने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की ग्रामीण विकास की दिशा में यह मॉडल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण, कृषि विविधीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ा गया है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी लाभ औषधीय खेती का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं है। खस, ब्राह्मी, बच और लेमनग्रास जैसी फसलें कई क्षेत्रों में कम पानी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खेती के विकल्प उपलब्ध करा सकती हैं। इनके विस्तार से भूमि उपयोग में विविधता और हरित आवरण बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध पारंपरिक स्वास्थ्य परंपरा को देखते हुए औषधीय पौधों का संरक्षण और कृषिकरण सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थानीय औषधीय ज्ञान और वनस्पति संसाधनों को आजीविका से जोड़ने की संभावनाएं व्यापक हैं। हालांकि औषधीय पौधों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी उपयोगों में वैज्ञानिक प्रमाण, उचित पहचान और विशेषज्ञ सलाह जरूरी है। इसलिए खेती के साथ गुणवत्ता, प्रसंस्करण और सुरक्षित उपयोग पर भी समान रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा।

धमतरी को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

धमतरी के औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के कृषिकरण मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित महाकुंभ-2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि जागरण के संयुक्त मंच पर जिले को औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के कृषिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद अन्य राज्यों के किसान, अधिकारी और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा इस मॉडल का अध्ययन किए जाने की बात भी सामने आई। यह किसी भी स्थानीय पहल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इससे स्थानीय प्रयोग को व्यापक स्तर पर अपनाए जाने की संभावना बढ़ती है।

अब 500 एकड़ तक विस्तार का लक्ष्य

पहले चरण की सफलता के बाद अब इस पहल को लगभग 500 एकड़ तक विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से 500 से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने की दिशा में काम किया जाना प्रस्तावित है। इस विस्तार की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, वैज्ञानिक सलाह, सिंचाई, बाजार, उचित मूल्य और समय पर भुगतान जैसी सुविधाएं कितनी प्रभावी ढंग से मिलती हैं। साथ ही बाजार की वास्तविक मांग के अनुरूप फसल चयन और खरीद व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना भी जरूरी होगा।

दुष्कर्म और हत्या; पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर आरोपी को किया गिरफ्तार

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना ने घटना की सूचना मिलते ही स्वयं मोर्चा संभालते हुए विशेष टीमें गठित कीं। करीब 50 पुलिसकर्मियों, डॉग स्क्वॉड, एफएसएल, तकनीकी टीम और सैकड़ों ग्रामीणों की पूरी रात चली सघन तलाश के बाद जंगल की झाड़ियों से मासूम का शव बरामद हुआ और आरोपी अनिल यादव को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार 5 अगस्त को बालिका स्कूल से यह कहकर छुट्टी लेकर निकली थी कि उसके पिता ने उसे बुलाया है, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। परिजनों द्वारा गांव और आसपास तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो चौकी झौतेश्वर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सूचना मिलते ही गोटेगांव पुलिस सक्रिय हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया। जंगल, खेतों और झाड़ियों में लगभग 7 से 8 घंटे तक लगातार खोज अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वॉड, तकनीकी टीम और वैज्ञानिक संसाधनों की भी मदद ली गई। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा के प्रति विशेष सतर्कता बरतें, विद्यालय आने-जाने के दौरान निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या डायल-112 पर दें।

क्या चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव कांग्रेस की संजीवनी बनकर उभरेंगे?

(पेज 1 का शेष)

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि संगठन को नई ऊर्जा देने और कार्यकर्ताओं का विश्वास मजबूत करने की है। ऐसे समय में पार्टी का झुकाव अनुभवी नेताओं की ओर होना स्वाभाविक माना जा रहा है। डॉ. चरणदास महंत ऐसे नेता हैं, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. चरणदास महंत कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने संगठन और संसदीय राजनीति दोनों में लंबा अनुभव अर्जित किया है। सांसद, केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका अनुभव उन्हें संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत नेता बनाता है। कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद और संगठन पर उनकी पकड़ उन्हें कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। वहीं सिंहदेव को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे सौम्य, अध्ययनशील और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले नेताओं में गिना जाता है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है जो राजनीतिक टकराव की बजाय संवाद और सहमति के माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं।

संगठन को मिल सकती है नई दिशा

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि मजबूत संगठन, प्रभावी नेतृत्व और स्पष्ट रणनीति से जीते जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस यदि अपने अनुभवी नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारियां देती है, तो इससे संगठन को नई दिशा मिल सकती है। हाल के समय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर लगे विभिन्न आरोपों और उनसे जुड़े राजनीतिक विवादों ने भी कांग्रेस के सामने नई परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। इन घटनाक्रमों के बाद पार्टी नेतृत्व संगठन की

छवि, रणनीति और नेतृत्व संरचना पर नए सिरे से विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि किसी भी आरोप का अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ऐसे विवाद अक्सर संगठनात्मक फैसलों को प्रभावित करते हैं। ऐसे समय में कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वह चुनावी तैयारी को केवल व्यक्तियों तक सीमित रखेगी या संगठनात्मक ढांचे को भी नए सिरे से मजबूत करेगी। यदि पार्टी आगामी चुनाव में प्रभावी चुनौती पेश करना चाहती है तो उसे बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना होगा, कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाना होगा और नेतृत्व की स्पष्ट भूमिका तय करनी होगी।

संगठनात्मक अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व

डॉ. महंत और डॉ. सिंहदेव की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि दोनों नेताओं की राजनीति अपेक्षाकृत संतुलित और संवाद आधारित रही है। दोनों नेताओं ने कई अवसरों पर संगठनात्मक अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर उनके नाम पर अपेक्षाकृत व्यापक सहमति बनने की संभावना व्यक्त की जाती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर भी आधारित रही है। सरगुजा और मध्य छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में इन दोनों नेताओं का प्रभाव कांग्रेस के लिए संगठनात्मक दृष्टि से उपयोगी माना जाता है। यदि इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्षेत्रीय संतुलन साधने में भी पार्टी को लाभ मिल सकता है। कांग्रेस के सामने यह भी चुनौती है कि वह युवा नेतृत्व और अनुभवी नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करे। केवल वरिष्ठता या केवल युवा चेहरों के सहारे चुनावी सफलता आसान नहीं होती। अनुभवी नेताओं के मार्गदर्शन और युवा कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का संतुलन ही संगठन को मजबूती प्रदान कर सकता है।

महंत और सिंहदेव बनेंगे प्रमुख चेहरा

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2028 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए निर्णायक माना जा रहा है। पार्टी यदि समय रहते संगठनात्मक बदलाव करती है, नेतृत्व की जिम्मेदारियां स्पष्ट करती है और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाती है तो चुनावी मुकाबले को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। डॉ. चरणदास महंत और डॉ. टी.एस. सिंहदेव का लंबा राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक समझ और अपेक्षाकृत संतुलित सार्वजनिक छवि उन्हें कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बनाती है। यदि पार्टी नेतृत्व वास्तव में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो इन दोनों नेताओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। आने वाले महीनों में कांग्रेस के संगठनात्मक निर्णय यह स्पष्ट करेंगे कि पार्टी किस रणनीति के साथ 2028 के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है। फिलहाल राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र यही है कि कांग्रेस अनुभवी नेतृत्व के भरोसे अपने संगठन को नई मजबूती देने की तैयारी में है और डॉ. चरणदास महंत तथा डॉ. टी.एस. सिंहदेव इस रणनीति के प्रमुख चेहरे बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा छत्तीसगढ़

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिक कल्याण को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का जो संकल्प लिया गया है वह जमीन पर उतर रहा है। पिछले ढाई साल में श्रम विभाग ने सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की मिसाल गढ़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक ऐतिहासिक पहल की हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सुशासन, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार से जोड़ते हुए श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। वहीं श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में विभाग ने श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ तेजी और सरलता से पहुंचाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, इन योजनाओ के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

लगभग 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित

श्रम विभाग की उपलब्धियों में सबसे उल्लेखनीय सफलता श्रमिक पंजीयन और हितलाभ वितरण रही है। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2026 के बीच लगभग 12.65 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया। लगभग 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया, जिन पर लगभग 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई। निर्माण श्रमिकों को लगभग 780 करोड़ रुपये तथा असंगठित श्रमिकों को लगभग 187 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। लाभ वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली लागू की गई है।

1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता

महिला श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र की 1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता प्रदान की गई। वहीं 'शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना' के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेधावी शिक्षा सहायता, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग तथा छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। हजारों विद्यार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे श्रमिक परिवारों के सपनों को नई उड़ान मिल रही है।

खाद्य विभाग की कार्रवाई, 338 किलो संदिग्ध घी जब्त, 4 सैंपल लैब भेजे

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने शहर स्थित चाहत मार्केटिंग पर औचक दबिश दी। निरीक्षण के दौरान टीम को गोवर्धन घी एवं नंद कृष्णा घी की गुणवत्ता पर संदेह हुआ, जिस पर दोनों ब्रांडों के 04 नमूने (सैंपल) जांच के लिए लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह राणा एवं कमलेश एस. दियावार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए मौके से 338 किलोग्राम संदिग्ध घी जब्त कर लिया। जब्त सैंपलों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ जिले में यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

सम्पादकीय

दतिया विधानसभा उपचुनाव: संगठन के लिए आत्ममंथन का अवसर

दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक सीट का नुकसान नहीं, बल्कि संगठन और रणनीति पर गंभीरता से विचार करने का अवसर है। मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया को भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। ऐसे में कांग्रेस के घनश्याम सिंह का भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों से पराजित करना निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह परिणाम उस धारणा को चुनौती देता है कि मजबूत संगठन और सत्ता की राजनीतिक ताकत किसी भी उपचुनाव में जीत की गारंटी दे सकती है। दतिया की कहानी को केवल इस उपचुनाव से जोड़कर देखना भी उचित नहीं होगा। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने भाजपा के तत्कालीन कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को 7,742 मतों से हराया था। यानी दतिया में भाजपा को लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। 2023 में भाजपा को 81,235 और कांग्रेस को 88,977 मत मिले थे। इस बार भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा के स्थान पर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। टिकट बदलने का निर्णय अपने साथ राजनीतिक संदेश भी लेकर आया। प्रत्याशी चयन के बाद स्थानीय स्तर पर असंतोष और विरोध की खबरें सामने आईं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी ने पार्टी के सामने यह चुनौती खड़ी कर दी कि वह चुनावी मैदान में उतरने से पहले अपने ही संगठन को कितनी मजबूती से एकजुट कर पाती है। चुनाव में हार का कोई एक कारण नहीं होता। मतदाता का निर्णय अनेक स्थानीय, राजनीतिक और सामाजिक कारकों का परिणाम होता है। इसलिए दतिया के परिणाम को केवल 'भितरघात' कहकर समाप्त कर देना भाजपा के लिए सबसे आसान, लेकिन शायद सबसे कम उपयोगी निष्कर्ष होगा। पार्टी को यह देखना होगा कि क्या स्थानीय कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्णयों से पूरी तरह सहमत थे, क्या उम्मीदवार और संगठन के बीच प्रभावी समन्वय बना, और क्या चुनाव अभियान जनता के स्थानीय सवालों से पर्याप्त रूप से जुड़ पाया। यहां कांग्रेस की रणनीति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। घनश्याम सिंह की जीत बताती है कि विपक्ष यदि स्थानीय समीकरणों को समझकर संगठनात्मक स्तर पर प्रभावी अभियान चलाए तो भाजपा के मजबूत माने जाने वाले क्षेत्रों में भी मुकाबला बदल सकता है। दतिया में कांग्रेस ने अपने पुराने आधार को बनाए रखने के साथ भाजपा की आंतरिक चुनौतियों का लाभ उठाया। हालांकि, इस जीत को कांग्रेस के व्यापक पुनरुत्थान का प्रमाण मानना भी जल्दबाजी होगी। एक उपचुनाव का परिणाम पूरे प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय नहीं करता।

भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब यह है कि वह इस हार से क्या सीखती है। चुनाव के बाद पार्टी ने दतिया जिला इकाई में बदलाव और आंतरिक समीक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यह संकेत सकारात्मक है, बशर्ते समीक्षा केवल जिम्मेदार लोगों की तलाश तक सीमित न रहे, बल्कि संगठन की वास्तविक कमियों को पहचानने का माध्यम बने। राजनीतिक दलों के लिए चुनावी हार असामान्य नहीं है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों जनता के निर्णय का हिस्सा हैं। असली कसौटी यह है कि कोई दल हार के बाद अपनी कमियों को स्वीकार कर कितना सुधार करता है। भाजपा के पास मजबूत संगठन, व्यापक कार्यकर्ता नेटवर्क और मध्य प्रदेश में सत्ता का अनुभव है। इसलिए दतिया की हार को संकट की अंतिम घंटी के बजाय चेतावनी की तरह देखना अधिक उचित होगा। दतिया का मतदाता यह संदेश दे रहा है कि राजनीतिक प्रभाव स्थायी नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में पुराना जनाधार तभी कायम रहता है जब संगठन जनता से निरंतर संवाद बनाए रखे, स्थानीय कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और उम्मीदवार चयन में जमीनी परिस्थितियों को पर्याप्त महत्व दिया जाए।

सियासी गहमागहमी

दतिया में टीम भंग कर क्या साबित करना चाहती है भाजपा?

दतिया में उपचुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश भाजपा ने स्थानीय संगठन की पूरी टीम भंग कर दी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नई टीम कौन बनाएगा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले से पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? क्या यह संगठन को मजबूत करने की कवायद है या चुनावी हार की जिम्मेदारी स्थानीय कार्यकर्ताओं के सिर डालने का प्रयास? दतिया में टिकट को लेकर उपजा असंतोष किसी से छिपा नहीं था। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के बाद जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी के सामूहिक इस्तीफे की स्थिति बनी थी। हार के बाद संगठन में बदलाव होना असामान्य नहीं है। लेकिन बदलाव का उद्देश्य यदि केवल यह संदेश देना हो कि हार की कीमत नीचे के कार्यकर्ता चुकाएंगे, तो इससे संगठन मजबूत होने के बजाय कार्यकर्ताओं में असुरक्षा पैदा हो सकती है। भाजपा स्वयं लंबे समय से बूथ स्तर के कार्यकर्ता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती रही है। दतिया में चुनाव से पहले भी कार्यकर्ताओं की भूमिका को निर्णायक बताया गया था। आखिर चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर ही लड़े जाते हैं। संगठन की नई इमारत पुराने कार्यकर्ताओं की नींव पर ही खड़ी होगी। इसलिए दतिया में टीम भंग करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह साबित करना होगा कि भाजपा अपने कार्यकर्ता की सुनती भी है और उसे सम्मान भी देती है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ी उथल-पुथल के संकेत

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों जिस तरह की राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है, उसने पार्टी के भीतर बड़े बदलाव की संभावनाओं को जन्म दिया है। संगठन में लंबे समय से चल रही खींचतान, नेतृत्व को लेकर अलग-अलग धड़ों की सक्रियता और चुनावी प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवाल अब सतह पर आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर व्यापक फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल संगठनात्मक बदलाव की नहीं, बल्कि नेतृत्व में भरोसा कायम करने की है। यदि पार्टी पुराने मतभेदों को सुलझाए बिना केवल पदों में बदलाव करती है, तो इसका असर सीमित ही रहेगा। जरूरत इस बात की है कि जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच संवाद बढ़े तथा निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय नेतृत्व को पर्याप्त महत्व मिले। दूसरी ओर, लंबे समय से सक्रिय राजनीतिक गुटबाजी को नजरअंदाज करना भी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में संगठन की कमजोरी का सीधा लाभ विपक्ष को मिलता है। इसलिए संभावित फेरबदल को किसी गुट को मजबूत करने के बजाय संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस में कौन-से चेहरे आगे आते हैं और किन नेताओं की भूमिका बदलती है, यह महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल संकेत यही हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बड़े संगठनात्मक पुनर्संयोजन के मुहाने पर खड़ी है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

देश के छात्रों ने system के फैलाए अंधेरे के बीच, अपने डर का सामना कर, रौशनी की मशाल जलाई है।

ये मशाल अब पूरे देश को अपने अधिकारों का रास्ता दिखा रही है।

BJP-RSS और अडानी के System को अब खतम, tata, bye-bye कहने का वक्त आ गया है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

आज भाजपा की सरकार हर स्तर पर आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय कर रही है। ऐसे में आदिवासी समुदाय को कांग्रेस सरकार के दौर की याद आने लगी है।

मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में आदिवासी हित के कई कार्य किए गए।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

अभिजीत दीपके बने युवा-केंद्रित आंदोलन के संस्थापक

समता पाठक/जगत प्रवाह

अभिजीत दीपके आज भारत के उभरते हुए युवा राजनीतिक और सामाजिक चेहरों में से एक हैं। वे विशेष रूप से युवाओं, विद्यार्थियों, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में आए हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व नाम औरंगाबाद) से संबंध रखने वाले दीपके ने डिजिटल संचार और सोशल मीडिया को जनभागीदारी का माध्यम बनाकर कम समय में व्यापक पहचान बनाई। वर्ष 2026 में उनका नाम 'कॉंकरोच जनता पार्टी' (CJP) नामक युवा केंद्रित आंदोलन के संस्थापक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ। अभिजीत दीपके का प्रारंभिक जीवन महाराष्ट्र में बीता। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने पुणे में पत्रकारिता की पढ़ाई की और आगे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री पूरी की। बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने भी जून 2026 में प्रकाशित अपने लेख में इसकी पुष्टि की कि दीपके ने पिछले वर्ष पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री पूरी की थी। उनकी शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली को काफी प्रभावित किया। जनसंपर्क, डिजिटल मीडिया, राजनीतिक संचार और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक विचार पहुँचाने की उनकी क्षमता बाद में उनके सार्वजनिक जीवन की प्रमुख विशेषता बनी।

अभिजीत दीपके ने राजनीति में सीधे चुनाव लड़ने के बजाय राजनीतिक संचार और डिजिटल अभियान के क्षेत्र से शुरुआत की। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार वे वर्ष 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया कार्यों में सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने डिजिटल कैंपेन और युवाओं तक राजनीतिक संदेश पहुँचाने की रणनीतियों पर काम किया। यही अनुभव आगे चलकर उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने समझा कि आज के समय में युवाओं तक किसी मुद्दे को पहुँचाने के लिए पारंपरिक राजनीतिक मंचों के साथ-साथ सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल भी आवश्यक है। मई 2026 में अभिजीत दीपके अचानक राष्ट्रीय चर्चा में आए। यह घटनाक्रम एक विवादित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, जिसमें बेरोजगार युवाओं को 'कॉंकरोच' कहे जाने की बात व्यापक रूप से चर्चा में आई। इसके जवाब में दीपके ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया। यदि ये 'कॉंकरोच' एक साथ आ जाएँ तो क्या होगा? उनका यह विचार तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते एक डिजिटल अभियान का रूप ले लिया। इसी अभियान से 'कॉंकरोच जनता पार्टी' यानी CJP का जन्म हुआ। प्रारंभ में इसे एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में यह बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों को उठाने वाला व्यापक युवा आंदोलन बन गया। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में CJP ने 2026 में परीक्षा व्यवस्था और कथित अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और युवा शामिल हुए। आंदोलन की प्रमुख मांगों में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, परीक्षा संबंधी समस्याओं पर जवाबदेही और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा शामिल थी। 20 जुलाई 2026 को संसद की ओर मार्च का प्रयास भी आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ तथा कई लोग घायल हुए। इसके बाद दीपके ने आगे के संसद मार्च को रोकने की घोषणा की, ताकि और युवाओं को चोट न पहुँचे, लेकिन उन्होंने आंदोलन जारी रखने की बात कही। अभिजीत दीपके की सबसे बड़ी विशेषता उनकी डिजिटल संवाद क्षमता मानी जाती है। उन्होंने सोशल मीडिया की भाषा, व्यंग्य और युवा संस्कृति को राजनीतिक मुद्दों से जोड़ने का प्रयास किया। उनके नेतृत्व में CJP का आंदोलन इंटरनेट से निकलकर सड़कों तक पहुँचा और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। आंदोलन ने हजारों युवाओं को संगठित किया और दीपके इसके प्रमुख चेहरों में उभरे। जुलाई 2026 के आंदोलन के बाद दीपके और CJP के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आंदोलन को आगे किस दिशा में ले जाया जाए। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार दीपके ने तत्काल चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के बजाय सामाजिक आंदोलन और युवाओं के मुद्दों पर काम जारी रखने पर जोर दिया है। उनका उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को संगठित रूप से सामने लाना और संस्थागत जवाबदेही की मांग को मजबूत करना बताया गया है।

भारत के आधुनिक सड़क विकास के शिल्पकार हैं कमलनाथ

(पेज 1 का शेष)

कमलनाथ ने केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला। मई 2009 से 2011 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री रहे। कैबिनेट मंत्री उनके कार्यकाल में सड़क अवसंरचना के विस्तार, ग्रामीण संपर्क बढ़ाने, राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण तथा विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की गईं। उनकी कार्यशैली का मूल उद्देश्य था कि भारत का विकास गांवों से लेकर महानगरों तक समान रूप से पहुंचे और सड़कें आर्थिक समृद्धि की नई राह बनें।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की मजबूत शुरुआत

कमलनाथ के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और उनके उन्नयन पर विशेष बल दिया गया। उस समय देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के अनुरूप बेहतर सड़क नेटवर्क की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने मंत्रालय की कार्यप्रणाली में तेजी लाने, लंबित परियोजनाओं को गति देने तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति मिली और कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। चार लेन और छह लेन सड़कों के विस्तार ने न केवल यात्रा को आसान बनाया बल्कि माल परिवहन की लागत कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेहतर सड़क संपर्क ने औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादों के विपणन और पर्यटन को नई गति प्रदान की। आज जिन अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों पर देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है, उनके विकास की प्रक्रिया में कमलनाथ के कार्यकाल का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मिली नई गति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कमलनाथ के कार्यकाल में प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। हजारों गांवों को सर्व मौसमीय सड़कों से जोड़ने का अभियान तेज हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पहुंचने का अर्थ केवल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि किसानों के लिए बाजार तक पहुंच, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय, मरीजों के लिए अस्पताल तथा ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सुनिश्चित करना था।

एक्सप्रेस-वे संस्कृति की आधारशिला

भारत में आधुनिक एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का विस्तार एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। कमलनाथ के कार्यकाल में देश में उच्च गुणवत्ता वाली नियंत्रित प्रवेश (कंट्रोल्ड एक्सेस) सड़कों की आवश्यकता पर गंभीरता से काम किया गया। कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की प्रारंभिक योजना, स्वीकृति और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका रही। इन प्रयासों ने भविष्य में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले आधुनिक एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। आज देश जिन अत्याधुनिक एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का लाभ उठा रहा है, उनकी अवधारणा और प्रारंभिक प्रक्रियाओं को गति देने में उस दौर की नीतिगत पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन

कमलनाथ ने पर्यावरण एवं वन मंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। उनके कार्यकाल में विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना निर्माण पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो। वन संरक्षण, पर्यावरणीय स्वीकृतियों में पारदर्शिता तथा टिकाऊ विकास की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की गईं। उनकी सोच स्पष्ट थी कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं।

मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों को मिला लाभ

कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में मध्यप्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। विशेष रूप से पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाने के प्रयासों ने क्षेत्रीय विकास को गति दी। बेहतर सड़क संपर्क के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार की सुविधाएं पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुईं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और सामाजिक विकास को नई दिशा मिली।

दीर्घकालिक सोच का परिणाम

सड़क निर्माण का वास्तविक लाभ वर्षों बाद दिखाई देता है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेस-वे परियोजना की योजना, स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्था और निर्माण में कई वर्ष लगते हैं। इसलिए आज दिखाई देने वाली अनेक परियोजनाओं की नींव पूर्ववर्ती सरकारों और मंत्रियों के कार्यकाल में रखी गई थी। कमलनाथ ने इसी दीर्घकालिक सोच के साथ सड़क अवसंरचना के विस्तार पर कार्य किया। उनके द्वारा शुरू की गई अनेक प्रक्रियाएं आगे चलकर देश के आधुनिक सड़क नेटवर्क के निर्माण में सहायक बनीं। सड़क परिवहन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से आधारभूत संरचना विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।

कश्मीर में हिंदुओं पर लक्षित आतंकी हमला

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में ईंट-भट्टे पर काम करने वाले दो हिंदू मजदूरों की आतंकियों ने नाम व धर्म पूछकर हत्या कर दी। इस हमले में 15 माह पहले पहलगाम में धर्म पूछकर 26 हिंदू पर्यटकों की गई हत्याओं का अनुकरण किया गया है। कुलगाम में मारे गए दोनों प्रवासी श्रमिक छत्तीसगढ़ के थे। इनके नाम भूपेंद्र भैना और दीपक रात्रे थे। ये बीते नो माह से यहां काम कर रहे थे। इस हमले की जिम्मेदारी लष्कर के मुखौटा संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) ने ली है। साथ ही आगे और भी हमलों की धमकी देकर बर्बर हत्यारे नो-दो ग्यारह हो गए। सुरक्षाबल इनकी तालाशी में लग गए हैं। इस हमले ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा किया है कि तमाम कोशिषों के बावजूद आतंकवाद बेलगाम क्यों दिखता है? जबकि पहलगाम में हुए हमले के बाद सेना ने आपरेशन सिंदूर अभियान चलाकर पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया था। यहां तक कि पाकिस्तान ने शरणागत की मुद्रा में आकर भारत के समक्ष घुटने टेक दिए थे। लेकिन उसका आतंकी जहर अभी उतरा नहीं है।

पाकिस्तान धर्म की घुट्टी पिलाकर 35 साल से भारत पर आतंकी हमले करता रहा है। लेकिन उसे सबसे मुकम्मल उत्तर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया था। लेकिन कुत्ते की पूंछ की तरह पाक की पूंछ टेढ़ी ही बनी हुई है। गैर कश्मीरियों और हिंदुओं की हत्या के लिए उसकी क्रूरता समाप्त नहीं हो रही है। जाहिर है, पाकिस्तान भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बदले को भूल गया है। उसे एक बार फिर करारा जवाब देना होगा। दरअसल इस समय पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में चल रहे आजादी के आंदोलन से भी जूझ रहा है। वहां भी उसने निर्ममता बरतते हुए 40 प्रदर्शनकारियों को भूनने का काम हाल ही में किया है। पाक की ये हरकतें इसलिए भी बरकरार हैं, क्योंकि ईरान हमले में उलझा अमेरिका उसकी पीठ थपथपाने में लगा है। ऐसे में भारत को अनेक कूटनीतिक कदम उठाकर पाकिस्तान को विवश करना होगा। अन्यथा वह आतंकियों को कश्मीर की धरती पर भेजकर हिंसा की इबारतें लिखता रहेगा। कुलगाम की घटना यह भी इंगित कर रही है कि घाटी में आतंकियों को पनाह एवं सूचनाएं स्थानीय लोगों से मिल रही हैं। अतएव आतंकियों को शरण देने वाले कश्मीर वासियों की खबर लेने की भी जरूरत है। अन्यथा मजहब के आधार पर हिंदुओं की हत्या का सिलसिला बना रहेगा।

याद रहे पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली थी। यह लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है, जो लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों की आतंकी हरकतों को ही अंजाम देता है। भारतीय सेना ने कोटली अब्बास में जिस आतंकी शिविरों को तबाह किया किया था, इसमें 1500 आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया था। मुरीदके में जिस मरकज तैयबा को ध्वस्त किया गया था, यहां लश्कर का मुख्यालय माना जाता है। यहीं से मुंबई हमले का प्रमुख आतंकी अजमल कसाब ने प्रशिक्षण लिया था। इस जबाबी कार्यवाही के बाद भारत की कूटनीति अत्यंत सफल दिखाई दी थी, क्योंकि भारत का तत्काल अमेरिका, रूस और जापान ने खुलकर समर्थन किया था। यह समर्थन मोदी ने वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए से जो मुहिम चलाई हुई है, उसका परिणाम थी। अतएव इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमापार स्थित ठिकानों से आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले संगठनों के खिलाफ सेना और सुरक्षाबलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह स्थिति बनी रहे, इस हेतु सेना लगातार अपनी रणनीति में गोपनीय परिवर्तन करते हुए आतंक के विरुद्ध मोर्चा संभाले हुए है। इसी का नतीजा है कि आतंकी हमलों में लगातार कमी आई है। बावजूद पहलगाम और कुलगाम जैसे लक्षित हमले किए जा रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान इस आतंक के छद्म युद्ध के बहाने अपनी क्रूरता जताता रहता है। कश्मीर में आतंक बने रहने का एक कारण यह भी है कि आतंकियों को मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम होने के कारण संरक्षण आसानी से मिल जाता है। यही कारण है कि रुक-रुककर आतंकी बिना किसी शोर-शराबे के मुस्लिम आबादी के बीच घुसपैठ करके हिंदुओं के विरुद्ध लक्षित हिंसा को परिणाम में बदलने में सफल हो जाते है। ऐसे हमलों में निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं।

अनुच्छेद-370 हटने के बाद भी हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण मजहबी कट्टरता पर चोट नहीं कर पाना है। गोया, साफ है कि यह समस्या अब राजनैतिक व संवैधानिक नहीं रह गई है, बल्कि अब धार्मिक चरमपंथ के रूप में सामने आ रही है। इस हिंसक उन्माद का सोच पाकिस्तान से निर्यात आतंकवाद तो है ही, घाटी में कुकुरमुत्तों की तरह मस्जिदों और मदरसों में फैला, वह शिक्षा का तंत्र भी है, जो आतंक की फसल बोने और उगाने का काम करता है। यही वजह है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनमें न तो अल्पसंख्यकों का जनसंख्यात्मक घनत्व बढ़ रहा है और न ही उन्हें नागरिक समानता के अधिकार मिल रहे हैं। कश्मीर में भी जिहादी चाहते हैं कि गैर-मुस्लिम या तो इस्लाम स्वीकार करें या फिर घाटी छोड़ जाएं।

मुस्लिमों की इस दोषपूर्ण मंशा को संविधान निर्माण के समय ही डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समझ लिया था। शेख अब्दुल्ला ने जब जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग की तो अंबेडकर ने सख्त लहजे में कहा था कि 'आप चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों की आर्थिक सुरक्षा करे, कश्मीरियों को संपूर्ण भारत में समानता का अधिकार मिले, लेकिन भारत और अन्य भारतीयों को आप कश्मीर में कोई अधिकार देना नहीं चाहते ? मैं देश का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ कोई अन्याय या विश्वासघात किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूं।' विडंबना देखिए कि मुस्लिम समाज देश में हर जगह बृहद हिंदू समाज के बीच अपने को सुरक्षित पाता है, किंतु जहां कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बीच रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। बावजूद नेहरू के अनावश्यक दखल से कश्मीर को विशेष दर्जा मिल गया। इस भिन्नता का संकट देश बंटवारे से लेकर अब तक भुगत रहा है। यही वजह है कि इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू, बौद्ध, सिख और दलित शरणार्थी के रूप में जम्मू-कश्मीर में ही ठहर गए थे, उन्हें मौलिक अधिकार धारा-370 हटने के बाद मिल पाए हैं। इनकी संख्या करीब 70-80 लाख है, ये 56 शरणार्थी शिविरों में सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से महरूम रहते हुए बद से बदतर जिंदगी का अभिशाप धारा-370 हटने से पहले तक भोगते रहे हैं।

जीएसटी चोरी, मनी लांड्रिंग और इनकम टैक्स चोरी का भी बनता बड़ा मामला?

(पेज 1 का शेष)

रसूख के दम पर इंद्रजीत में HC में लगाया मानहानि का केस, HC ने नकारा

इंदरजीत सिंह ने अपने रसूख के दम पर मानहानि का मामला खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट में मामला टिक नहीं सका। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच में कमियां पाई और अंततः याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कथित मानहानिकारक भाषा के आधार पर आईटी एक्ट की धारा 67 लागू नहीं की जा सकती। इंदरजीत सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके खिलाफ व्हाट्सएप पर मानहानिकारक संदेश भेजे गए। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये संदेश आशीष मिशाल ने भेजे थे। पुलिस ने इसी आधार पर मामला दर्ज किया था। मामले में आरोप था कि व्हाट्सएप के जरिए एक संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें एक सीमेंट कंपनी और उसके अधिकारियों पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी, कोयला चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के आरोप लगाए गए थे। जिसमें इंद्रजीत ने कहा था कि इससे उसकी बदनामी हुई है। रौब जमाने के लिए इंद्रजीत में HC में मानहानि का केस लगाया था। सुनवाई के बाद HC ने नकारा दिया था। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इंदरजीत सिंह का मोबाइल फोन जांच के दौरान जब्त नहीं किया गया, जबकि कथित व्हाट्सएप संदेश सबसे पहले उसी मोबाइल पर प्राप्त हुए थे। इसी कारण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की धारा 65B में कमी पाई गई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी व्हाट्सएप संदेश में यदि किसी कंपनी या व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हों तो वह मानहानि का मामला हो सकता है, लेकिन केवल इसी आधार पर उसे आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री नहीं माना जा सकता।

1500 ट्रकों से लोहे का अवैध कारोबार!

भिलाई पावर हाउस और हथखोज क्षेत्र में HTC का मतलब हिंदुस्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी से है। इसके मुख्य कर्ताधर्ता और डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह हैं। यह वही बिजनेस ग्रुप है जिसकी शुरुआत दलवीर सिंह उर्फ़ वीरा सिंह द्वारा की गई थी और आज इस बड़े कारोबारी साम्राज्य को इंद्रजीत सिंह संभाल रहे हैं। वह भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, SBS हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इनके पास 1500 से भी अधिक ट्रकों और ट्रेलरों का बड़ा नेटवर्क है।

धान परिवहन में भी अवैध कब्जा

इंद्रजीत के एसोसिएशन ने प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर पूरी तरह से अवैध कब्जा कर लिया है। धान परिवहन में इनकी गाडियां चलती हैं। एक नम्बर की प्लेट को कई ट्रकों में लगा देते हैं। इनका मुख्य बिजनेस भिलाई स्टील प्लांट और अन्य बड़ी औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले लोहे, स्टील, कोयले और भारी मशीनों को देश के कोने-कोने में ट्रांसपोर्ट करने का है। इनके पास 1500 से भी अधिक ट्रकों और ट्रेलरों का बड़ा नेटवर्क है। कंस्ट्रक्शन और सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी इंडस्ट्रियल और सरकारी स्तर पर बड़े सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्थमूविंग से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है। स्टील ट्रेडिंग और डीलिंग भिलाई के स्थानीय स्टील रोलिंग मिलों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर आयरन और स्ट्रक्चरल स्टील की ट्रेडिंग का काम भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इनका मुख्य ऑफिस और ऑपरेशनल बेस पॉवर हाउस और हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया (भिलाई) में केंद्रित है। इनका नेटवर्क छत्तीसगढ़ के अलावा देश के प्रमुख इंडस्ट्रियल हब, बंदरगाहों और माइनिंग एरिया (ओडिशा, झारखंड, मध्यप्रदेश) से जुड़ा हुआ है, जहाँ भिलाई का स्टील भेजा जाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप में भी इनकी संलिप्तता है। इंद्रजीत कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

राजनेताओं और आला अधिकारियों की मिलीभगत से बढ़ा कारोबार

भिलाई स्टील प्लांट के मार्केटिंग डिविजन के अधिकारियों की भी मिलीभगत रहती है और नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। यह ट्रांसपोर्टर थाना भट्ठी के सभी पुलिस वालों को घूस देता है। मतलब यह है कि दुर्ग जिले के सभी सम्बन्धित अधिकारी इस लोहा चोरी के धंधे में लिप्त हैं।

अब नहीं तो कब? भूजल संचयन की तत्काल आवश्यकताएँ

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

जल ही जीवन है, लेकिन आज बढ़ती आबादी, शहरीकरण और अनियोजित विकास के कारण जल संकट गंभीर होता जा रहा है। आज जल संकट समूचे विश्व की गंभीर समस्या है। हालात इतने खराब है कि दुनिया के 37 देश पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। इनमें सिंगापुर, पश्चिमी सहारा, कतर, बहरीन, जमैका, सऊदी अरब और कुवैत समेत 19 देश ऐसे हैं जहां पानी की आपूर्ति मांग से बेहद कम है। दुःख की बात यह है कि हमारा देश इन देशों से सिर्फ एक पायदान पीछे है। असलियत यह है कि दुनिया में पांच में से एक व्यक्ति को साफ पानी तक की पहुंच नहीं है। कितनी दुखदाई स्थिति है कि दुनिया में नदियों के मामले में सबसे अधिक सम्पन्न हमारे देश की तकरीब साठ करोड़ से ज्यादा आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है और देश के तीन चौथाई घरों में पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। देश की यह स्थिति तब है जबकि यहां मानसून बेहतर रहता है। यदि जल गुणवत्ता की जाए तो इस मामले में हमारा देश निचले पायदान पर है। यह हमारे पानी के मामले में बदहाली का सबूत है। मानसून के दौरान कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, तो कहीं वर्षा की कमी से जलाशय सूखने लगते हैं। जुलाई 2026 तक देश के 166 प्रमुख जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का केवल लगभग 38 प्रतिशत पानी उपलब्ध था, जबकि कई जलाशयों में भंडारण सामान्य से काफी कम रहा। यह सच है कि भूजल पानी का महत्वपूर्ण श्रोत है। पृथ्वी पर होने वाली जलापूर्ति अधिकतर भूजल पर ही निर्भर है। वह चाहे सरकारी मशीनरी हो, उद्योग हो, कृषि क्षेत्र हो या आमजन सभी ने इसका इतना दोहन किया है जिसका नतीजा भूजल के लगातार गिरते स्तर के चलते जल संकट की भीषण समस्या के रूप में हमारे सामने है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में स्थिति कितनी विकराल हो सकती है। इसे उसी स्थिति में रोका जा सकता है, जबकि पानी समुचित मात्रा में रिचार्ज हो, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी का दोहन नियंत्रित हो, संरक्षण हो, भंडारण हो ताकि जमीन के अंदर प्रवेश कर सके। ऐसे समय में वर्षा जल संचय केवल पर्यावरण संरक्षण का उपाय नहीं, बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है। घरों, विद्यालयों, कार्यालयों और अपार्टमेंटों की छतों से वर्षा का पानी पाइप के माध्यम से टंकियों या भूमिगत रिचार्ज संरचनाओं में पहुंचाया जा सकता है। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा, पेयजल की उपलब्धता सुधरेगी और गर्मियों में जल-संकट कम होगा। सरकार को वर्षा जल संचय को भवन-निर्माण अनुमति से जोड़ने के साथ-साथ पुराने भवनों में भी रिचार्ज पिट बनवाने चाहिए। नागरिकों को छतों की सफाई, जल-संग्रह टंकियों की देखभाल और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूक होना होगा। यदि आज वर्षा की हर बूंद बचाई गई, तभी कल की प्यास बुझाई जा सकेगी। वर्षा जल संचय सचमुच समय की मांग है।

मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ!

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर अब थम गया है, परिणाम सामने हैं और कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया पूरे जोरों पर है। जहाँ कुछ युवाओं को उनके मनपसंद कॉलेज और कोर्स मिल गए हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो अपनी उम्मीदों के मुताबिक सफलता न मिलने से थोड़े निराश हैं। आज हम इन्हीं युवाओं से बात करेंगे। याद रखिए, जीवन संभावनाओं से भरा है। अपनी कथित असफलता को एक अनुभव के तौर पर लें और इससे सीखकर सफलता की ओर बढ़ें। खुद से बस इतना कहें: "मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ!" सवाल यह नहीं है कि आप सफल हुए या नहीं, सवाल यह है कि आप सीखकर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। इस साल मध्य प्रदेश में विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं और उनके परिणामों ने हज़ारों छात्रों के जीवन में नए मोड़ लाए हैं। ये परिणाम सिर्फ अंकों का खेल नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा भी हैं। याद रखिए, जीवन कभी रुकता नहीं; यदि एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा हमेशा खुलता है। यदि आपका चयन इस बार नहीं भी हो पाया है, तो इसे एक रुकावट नहीं, बल्कि रणनीति को फिर से सोचने का मौका समझें। यह समय है अपनी गलतियों से सीखने का, अपनी कमजोरियों पर काम करने का, और अपनी राह को और मजबूत बनाने का। आपकी दुनिया यहाँ नहीं रुकेगी; बल्कि यह एक नई शुरुआत है, जहाँ आप और भी बेहतर होकर आगे बढ़ेंगे।

हर चुनौती में छिपा होता है एक और अवसर

दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षा के रूप में लाखों छात्रों को एक और मौका दिया, यह साबित करते हुए कि एक असफलता कभी भी अंत नहीं होती। 17 जून से 5 जुलाई 2025 तक हुई इन परीक्षाओं के माध्यम से कई छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी और अब वे इसे पास करने के बाद गर्व के साथ कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। यह उनकी दृढ़ता और इच्छाशक्ति का प्रमाण है कि उन्होंने एक नया रास्ता बनाया। याद रखिए, जीवन कभी रुकता नहीं; यदि एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा हमेशा खुलता है।

JEE (Mains & Advanced) और NEET जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में सफल हुए छात्र काउंसलिंग के ज़रिए प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। यदि आप पीछे रह गए हैं, तो निराश न हों! यदि आपका चयन इस बार नहीं भी हो पाया है, तो इसे एक रुकावट नहीं, बल्कि रणनीति को फिर से सोचने का मौका समझें। एक परीक्षा में पिछड़ना आपके सपने को खत्म नहीं करता, बल्कि यह उसे और मजबूत करता है। यह आपको सिखाता है कि आपको कहाँ और कैसे सुधार करना है। यह समय है अपनी गलतियों से सीखने का, अपनी कमजोरियों पर काम करने का, और अपनी राह को और मजबूत बनाने का। आपकी दुनिया यहाँ नहीं रुकेगी; बल्कि यह एक नई शुरुआत है, जहाँ आप और भी बेहतर होकर आगे बढ़ेंगे। आप इससे सीखकर और भी मजबूत इरादों के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। यह दुनिया आगे बढ़ेगी, और आप भी, नए अवसरों और बेहतर तैयारियों के साथ!

- अब क्या करें- अपनी सीख को दिशा बनाएं
- आप काउंसलिंग प्रक्रिया में सतर्क रहें, समय पर सही विकल्प चुनें।
- कॉलेज का चुनाव करते समय सिर्फ रैंक या नाम न देखें, अपनी रुचि और संस्थान की विशेषज्ञता को प्राथमिकता दें।
- उच्च शिक्षा का यह नया अध्याय आपकी खुद की पहचान और आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम है। आप इसे मजबूती से उठाएं।
- यदि परिणाम अपेक्षित नहीं रहा: यह हार नहीं, सीखने का मौका है!
- आप अन्य विकल्पों (डिप्लोमा, स्किल कोर्स, फॉर्म भरने के नए मौके, निजी संस्थान आदि) को तलाशें।
- अगली परीक्षा की तैयारी ठोस प्लानिंग से करें, पिछली गलती दोहराएं नहीं।
- और सबसे ज़रूरी- खुद पर विश्वास बनाए रखें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है कांवड़ यात्रा

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व एवं राज्य सरकार की प्रभावी व्यवस्थाओं के कारण उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित, सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता तथा कानून-व्यवस्था के लिए किए गए व्यापक प्रबंधों का सकारात्मक परिणाम यह है कि अब तक 2 करोड़ 19 लाख 70 हजार से अधिक शिवभक्त पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर सकुशल प्रस्थान कर चुके हैं। वहीं 06 अगस्त 2026 को सायं 6 बजे तक एक ही दिन में 39 लाख 15 हजार कांवड़ यात्री गंगाजल लेकर लौटे। प्रदेश भर में कांवड़ यात्रियों के लिए निर्बाध यातायात, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि लाखों शिवभक्त शांतिपूर्ण, सुरक्षित और तेजी से अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं तथा राज्य सरकार की व्यवस्थाओं की खुले मन से सराहना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सेवा का महापर्व है। उन्होंने सभी कांवड़ यात्रियों, शिवभक्तों, स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सहयोग, समन्वय और अनुशासन से कांवड़ यात्रा 2026 का सफल एवं सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होगा तथा उत्तराखंड एक बार फिर उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और अतिथि सत्कार की अपनी गौरवशाली परंपरा को सशक्त रूप से स्थापित करेगा।

नगर परिषद द्वारा निर्मित सार्वजनिक मंच के नामांतरण पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर परिषद द्वारा शुक्रवारा शंकर मंदिर प्रांगण में पुराने सार्वजनिक मंच को तोड़कर लाखों रूपए की लागत से नया सार्वजनिक मंच तैयार किया है, जिसके शिलालेख पर सांस्कृतिक रामलीला मंच नाम दिया गया है। मंच के नामांतरण को लेकर नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने सवाल खड़े किए हैं एवं परिषद अध्यक्ष से पूछा है कि यह जो मंच जो कि नगर परिषद की राशि से बना है क्या सिर्फ रामलीला मंडल के लिए बना है या यह सार्वजनिक मंच रहेगा क्योंकि इससे पहले सनातन धर्मशाला में रामलीला मंडल को नगर परिषद ने कमरा दिया है। उसके सामने भी रामलीला मंडल अतिक्रमण कर रहा है। जबकि उसे इसका कोई अधिकार नहीं है क्योंकि रामलीला मंडल में बैठे कुछ पदाधिकारी धर्म के नाम पर एकाधिकार स्थापित करने में लगे हुए हैं, जो आगे भी धर्म के नाम पर मंच पर एकाधिकार स्थापित करेंगे। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने अध्यक्ष से पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति शहर में सार्वजनिक आयोजन करवाना चाहते हैं तो क्या रामलीला मंडल से अनुमति लेना पड़ेगी या नगर परिषद के आधिपत्य में ही रहेगा क्योंकि जिस तरह से अपने नामांतरण किया है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मंच सिर्फ रामलीला मंडल के लिए बना है अन्य कार्यों के लिए नहीं बना। नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज अपने निजी हित के लिए शासकीय राशि से बने मंच को सिर्फ एक रामलीला मंडल के नाम से कर देना अनुचित है और असंवैधानिक है तथा जनभावनाओं के विपरित है। क्योंकि रामलीला मंडल के कुछ लोगों का एक समूह है कोई शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने इस संबंध में परिषद अध्यक्ष से उनकी नीति और नीयत क्या है स्पष्ट करने की सलाह दी।

सेवा सेतु
जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुईं **त्वरित, पारदर्शी और आसान**

520
शासकीय सेवाएं

घर बैठे, एक क्लिक में

नागरिकों के लिए सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं

R.O. No. : 13930/ 2

95.9%
आवेदनों का निराकरण

- **38 लाख+** आवेदन
- **16,700+** सेवा केंद्र
- **36 विभाग** एक मंच पर

प्रमुख सेवाएं

- ✓ **जाति प्रमाण** पत्र
- ✓ **आय प्रमाण** पत्र
- ✓ **निवास प्रमाण** पत्र
- ✓ **विवाह प्रमाण** पत्र
- ✓ **राशन कार्ड** सेवाएं
- ✓ **पेंशन** योजनाएं
- ✓ नाम **परिवर्तन सेवा**
- ✓ व्यापार **लाइसेंस**

अधिक जानकारी हेतु **स्कैन करें**

जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार

sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)